भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 253

बुधवार, दिनांक 05 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

प्रधान मंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए वित्तीय आवंटन

***253. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:**

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषकर सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए बजट को दर्शाने वाली प्रधान मंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम- एसजीएमबीवाई) के लिए बजट 2026-27 में नवीकरणीय ऊर्जा के वित्तीय आवंटन में वृद्धि की गई है और यदि हां, तो उन कार्यनीतिक प्राथमिकताओं का ब्यौरा क्या है जिसके आधार पर यह आवंटन किया जाता है;

(ख) वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार के लक्ष्यों के ब्यौरे सहित और तेजी से अपनाई जाने वाली प्रणालियों के रूप में रूफटॉप संस्थापनाओं की संख्या कितनी बढ़ी है और इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल के माध्यम से संपार्श्विक-मुक्त ऋण वाली प्रणालियों के लिए प्रति परिवार राजसहायता से सौर ऊर्जा की सुलभता सुगम हुई है और यदि हां, तो इस संबंध में पंजीकरण और संस्थापन कार्य पूरा किए जाने संबंधी दरों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या घरेलू विनिर्माण के लिए कर प्रोत्साहनों के साथ-साथ बैटरी भंडारण, पूंजीगत वस्तुओं और सौर ग्लास आदानों पर शुल्क छूट का उद्देश्य एक आत्मनिर्भर सौर ऊर्जा पारितंत्र का निर्माण करना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या वितरण घाटे को कम करते हुए और वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को पूरा करते हुए, उक्त योजना उपभोक्ताओं को उपभोक्ता के बजाए अपनी स्वयं की बिजली पैदा करने वाले सह-उत्पादक (प्रोज्यूमर) में बदल देती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा शिक्षा मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

'प्रधान मंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए वित्तीय आवंटन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 05.08.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 253 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का बजट वर्ष 2025-26 के संशोधित बजट स्तर के चरण में ₹25,301.22 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान (BE) के चरण में ₹32,914.67 करोड़ किया गया है। इसी प्रकार, पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSG: MBY) के लिए बजट वर्ष 2025-26 के संशोधित बजट अनुमान (RE) के चरण में ₹17,000 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान (BE) के चरण में ₹22,000 करोड़ कर दिया गया है। PMSG: MBY के बजट में यह वृद्धि मुख्यतः योजना के अंतर्गत आवासीय परिवारों द्वारा रूफटॉप सौर (RTS) प्रणालियों को तेजी से अपनाए जाने के कारण हुई है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों, जिनमें समयबद्ध रूप से सब्सिडी का वितरण तथा डिजिटल पोर्टलों के माध्यम से Collateral-free loans की समय पर स्वीकृति को सुगम बनाना शामिल है, जिसके फलस्वरूप योजना के प्रारंभिक कार्यान्वयन चरण में जहाँ एक लाख परिवारों को शामिल करने में कुछ माह का समय लगता था, वहीं अब लगभग 6 दिन का समय लगता है।

फरवरी 2024 में शुरू की गई PMSG: MBY, जो एक मांग-संचालित योजना है, के तहत कुल 77,44,376 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुल मिलाकर 14.8 गीगावाट की क्षमता स्थापित की गई है, जिससे 50 लाख से अधिक परिवारों को लाभ हुआ है और दिनांक 04.08.2026 तक देश भर में 28,024 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) जारी की गई है।

(घ): सौर ग्लास के स्वदेशी मैन्युफेक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने सौर ग्लास के मैन्युफेक्चरिंग में उपयोग होने वाले सोडियम एंटीमोनेट (Sodium Antimonate) के आयात पर मूल सीमा शुल्क (BCD) को समाप्त कर दिया है।

इसके अलावा, देश में बैटरी भंडारण के लिए स्वदेशी मैन्युफेक्चरिंग क्षमता को बढ़ावा देने तथा आत्मनिर्भर इकोसिस्टम के विकास के उद्देश्य से, विद्युत वाहनों तथा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) में उपयोग होने वाली बैटरियों के लिए लिथियम-आयन सेलों के मैन्युफेक्चरिंग हेतु आवश्यक निर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं, मशीनरी एवं उपकरणों के आयात पर मूल सीमा शुल्क (BCD) से छूट प्रदान की गई है।

(ड.): रूफटॉप सौर (RTS) प्रणालियों वाले परिवार अपनी आवश्यकता के लिए स्वयं विद्युत का उत्पादन करते हैं तथा प्रचलित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विनियमों के अनुसार अतिरिक्त विद्युत को ग्रिड में निर्यात भी कर सकते हैं। चूँकि रूफटॉप सौर (RTS) प्रणालियाँ वितरण नेटवर्क के उपभोक्ता छोर (Consumption End) अथवा अंतिम छोर (Tail End) पर स्थापित की जाती हैं, इसलिए इनसे वितरण हानियां कम होती हैं। पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSG: MBY) के अंतर्गत दिनांक 31.07.2026 तक 14.65 गीगावाट से अधिक सौर विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है, जो वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता के लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान दे रही है।

****